

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

क्रमांक / 11486/2025

उज्जैन, दिनांक - 23-12-2025

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण,
जिला न्यायालय उज्जैन,
तहसील न्यायालय बड़नगर/महिदपुर/नागदा/खाचरौद/तराना

विषय - ई-समन/वारंट की जानकारी प्रेषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ - माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का पत्र क्रमांक No. C/7481
Reg.(I.T.)/2025 dated 18-12-2025

—0—

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से न्यायालयों द्वारा सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई-समन जारी किया जा रहा है अथवा नहीं और यदि नहीं किया जा रहे हैं तो उन न्यायालयों के नाम जो कि भौतिक समन जारी कर रही है, ई-समन जारी किये जाने में आने वाली समस्या एवं उचित सुझाव हेतु रिपोर्ट मांगी गई है।

अतः संलग्न प्रारूप में जानकारी दिनांक 24.12.2025 को शाम 04:00 बजे तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार,

 23.12.25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.

High Court of Madhya Pradesh: Jabalpur

No. C/7481 /Reg. (I.T.)/2025

Dated: 17.12.2025

18

To,

**The Principal District & Sessions Judge
(All in the State of Madhya Pradesh)**

Subject: Regarding submission of information pertaining to issuance of e-Summons.

Respected Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform that a meeting was held on 16.12.2025 with the Hon'ble Home Secretary, Ministry of Home Affairs, to deliberate upon various issues.

During the said meeting, attention was drawn to the fact that in some locations, physical summons are being issued instead of e-summons. The High Court of Madhya Pradesh has been consistently emphasizing on issuance of summons through online modes.

In view of the above, it is requested that a report be submitted indicating whether e-summons through the CIS are being issued by the courts under your jurisdiction. In cases where e-summons are not being issued, the names of the Courts where physical summons are being issued may be specified, along with detailed reasons for issuing physical summons instead of e-summons. The difficulties, if any, being faced by the concerned judicial officers in issuing e-summons may also be clearly stated and the appropriate remedial measures may be taken at your end.

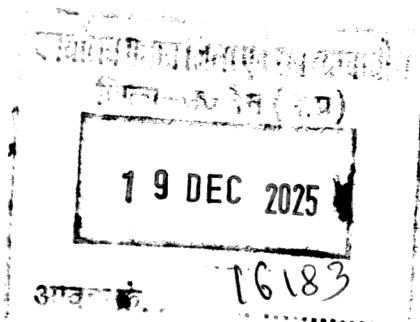
The report may be submitted within a period of seven days to enable further action in the matter.

M. B. Jaiswal

Dharminder Singh
17/12/2025

**DHARMINDER SINGH
REGISTRAR GENERAL**

JSA
C/O
18.12.25
82



ई-समन/वारंट की जानकारी प्रेषित करने

न्यायालय का नाम		हों या नहीं में जवाब उल्लेखित करें।	यदि नहीं किये जा रहे हैं तो उसका कारण उल्लेखित करें।	यदि कोई सुझाव हो तो उल्लेखित करें।
	क्या आपके न्यायालय में ई-समन ऑनलाईन सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं।			

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर